



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2017/भाद्र 31, 1939

No. 251]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2017/BHADRA 31, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितंबर, 2017

प्रकरण सं. एसएसआर- 14/2017

(निर्णयिक समीक्षा जाँच)

विषय : यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'मेलामाइन' के आयातों से संबंधित निर्णयिक समीक्षा पाटनरोधी जाँच की शुरूआत

सं. 7/14/2017-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

2. जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 01.06.2012 की अधिसूचना सं. 14/35/2010-डीजीएडी द्वारा यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'मेलामाइन' के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। इस सिफारिश के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 08.10.2012 की अधिसूचना सं. 48/2012-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा निश्चयात्मक शुल्क लगाया गया था।

समीक्षा हेतु अनुरोध

3. यतः नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9क(5) के अनुसार उक्त अधिनियम के अधीन लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि उससे पहले न हटाया जाए तो उनके लागू होने की तारीख से पॉन्च वर्षों के बाद वह निष्प्रभावी हो जाते हैं यदि उससे पहले प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई समीक्षा में यह निष्कर्ष निकलता है कि शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की आशंका है। उक्त के अनुसार प्राधिकारी के लिए उपाय की समाप्ति की तारीख से तर्कसंगत समयावधि पहले घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत

रूप से साक्षात्कृत आवेदन के आधार पर इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृति होने की आशंका है।

4. और यतः गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि. (जिसे आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया और जापान (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'मेलामाइन' के आयातों से संबंधित निर्णयिक समीक्षा पाटनरोधी जाँच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

समीक्षा के लिए आधार

5. लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध इस बात पर आधारित है कि संबद्ध देशों/क्षेत्रों से संबद्ध वस्तु का पाटन जारी है और यदि शुल्क हटाया जाता है तो उसके जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है क्योंकि संबद्ध देशों/क्षेत्रों के पास अतिरिक्त क्षमता और अन्य कारक हैं।

6. और यतः प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि याचिका में पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना की जाँच करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरूआत का उचित ठहराते हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जाँच की शुरूआत करते हैं।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

7. विचाराधीन उत्पाद जिसपर शुल्क लागू है 'मेलामाइन' है।

8. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 01.06.2012 के अंतिम जाँच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद के दायरे को निम्नानुसार परिभाषित किया :

'7. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद मेलामाइन है, जो एक स्वादहीन, गंधरहित और गैर-विषैला पदार्थ है। मेलामाइन फार्मेल्डीहाइड रेजिन का प्रयोग लेमिनेट्स के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें अच्छी कठोरता, खरोच, स्टेन, जल और ताप का प्रतिरोध होता है। कुछ विद्युतीय प्रयोगों में प्रयुक्त लेमिनेट्स में उच्च मैकेनिकल मजबूती, उच्च ताप प्रतिरोध और उत्तम विद्युत इंसुलेटिंग गुण होते हैं। एस्बेस्टास से युक्त मेलामाइन रेजिन में काफी अधिक डाइलेक्ट्रिक मजबूती और उच्च प्रतिरोध होता है। सबसे अच्छी आयामी स्थिरता के अलावा, मेलामाइन फार्मेल्डीहाइड माइलिंग पाउडर स्पष्ट और चमकीले रंग देता है, आसानी से ढल जाता है और सतही खरोच का प्रतिरोध करता है। मेलामाइन की फार्मेल्डीहाइड से प्रतिक्रिया होती है और सौन्दर्य और सुविधा के अनेक उत्पादों को बनाने के लिए रेजिन और मोलिंग पाउडर में निर्मित किया जाता है। मेलाइन का प्रयोग मेलामाइन फार्मेल्डीहाइड बनाने में किया जाता है जो बाद में पश्चवर्ती उत्पादों के उत्पादन के प्रयोग होता है।'

8. संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अधीन उपशीर्ष 29336100 में वर्गीकृत किया जाता है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संदर्भ के प्रयोजनार्थ है और वर्तमान जाँच पर इसका कोई वाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा।'

9. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। जैसा याचिकाकर्ता ने बताया है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमों के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अंतः वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित

संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' मानते हैं।

घरेलू उद्योग

10. संबद्ध देशों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णयिक समीक्षा हेतु वर्तमान याचिका गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि. द्वारा दायर किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक हैं। मूल जाँच में भी यही जाँच परिणाम थे। याचिकाकर्ताओं का उत्पादन भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। अतः याचिकाकर्ता नियमावली के अर्थ के भीतर योग्य है और घरेलू उद्योग है।

निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

11. घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत करते हैं ताकि जाँच की जा सके कि क्या दिनांक 08.10.2012 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 48/2012-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया/लागू संबद्ध वस्तु पर शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है और क्या शुल्क को जारी रखना आवश्यक है।

संबद्ध देश

12. वर्तमान जाँच में शामिल देश यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया और जापान (जिन्हें संबद्ध देश भी कहा गया है) हैं।

सामान्य मूल्य

13. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में सार्वजनिक डोमेन में विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता के अभाव में, सबद्ध देशों में सामान्य मूल्य का अनुमान उत्पादन लागत के आधार पर कच्ची सामग्रियों की प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत पर विचार करते हुए और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों जमा तर्कसंगत लाभ को विधिवत रूप से समायोजित करके लगाया गया है।

निर्यात कीमत

14. याचिकाकर्ता ने डीजीसीआईएंडएस से प्रकाशित आकड़ों के आधार पर संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का दावा किया है। कारखाना-द्वारा निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़े पर व्यय, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के संबंध में समायोजनों का दावा किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।

पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से अधिक है जिससे पता चलता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन के निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक होने और काफी अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। इंडोनेशिया के मामले में, जहां कोई आयात नहीं हुए हैं, प्राधिकारी ने पाटन और क्षति की संभावना की प्रथम दृष्टया जाँच की है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

16. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए विचार किया गया है। याचिकाकर्ता ने पाटित आयातों की समग्र रूप से और उत्पादन की दृष्टि से बढ़ी हुई मात्रा कम कीमत पर बिक्री और घरेलू उद्योग के लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद प्रवाह पर भारी परिणामी प्रतिकूल प्रभाव के परिणामस्वरूप कथित पाटन के फलस्वरूप क्षति होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति और/या पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में उसकी पुनरावृति होने के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने पर विचार करने के लिए निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

जाँच अवधि

17. वर्तमान जाँच में जाँच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 (12 महीने) की है। तथापि क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल 13–मार्च 14, अप्रैल 14–मार्च 15, अप्रैल 15–मार्च 16 और जाँच अवधि के आकड़ों पर विचार किया गया है। इसके अलावा, पीओआई के बाद के आकड़ों के संभावना विश्लेषण पर विचार किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

18. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें।

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

समय-सीमा

20. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजा जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकॉर्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए।

23. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की पाँच (5) प्रतियां अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।

24. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है ,पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध /रिकॉर्डी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

26. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

27. किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

28. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

29. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2017

Case No. SSR- 14/2017**(Sunset Review Investigation)**

Subject : Initiation of Sunset review Anti-dumping investigation concerning imports “Melamine” originating in or exported from European Union, Iran, Indonesia and Japan.

F. No. 7/14/2017-DGAD.—Having regard Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules):

2. Where the designated Authority Vide notification No. F. No. 14/35/2010-DGAD dated 01.06.2012 recommended imposition of Anti-dumping duty on imports of Melamine originating in or exported from European Union, Iran, Indonesia and Japan. On the basis of such recommendation ministry of Finance imposed definitive duty vide notification No. 48/2012-Customs (ADD) dated 08.10.2012.

Request for Review

3. Whereas, in terms of Section 9 A (5) the Customs Tariff Act, 1995, read with Rule 23 of the Rules, the antidumping duty imposed under the said Act shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, unless in a review, initiated before the expiry of the duty, the Designated Authority concludes that the cessation of the duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. And whereas Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd.(hereinafter referred to as the petitioner) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) for initiation of sunset review anti-dumping investigation and continuation of anti-dumping duties concerning imports of ‘Melamine’ (hereinafter also referred to as subject goods), originating in or exported from European Union, Iran, Indonesia and Japan (hereinafter also referred to as the subject countries)

Grounds for review

5. The request is for continuation of the antidumping duties in force on the grounds that dumping subject goods from the subject countries/territories have continued and is likely to continue and recur if the duties are revoked because of the excess capacities in the subject countries/territories and other factors.

6. And whereas, on finding *prima facie* that sufficient evidence in the petition to initiate an investigation to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, to justify an initiation of sunset review anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry concerning imports of the subject goods from subject countries.

Product under consideration and Like Article

7. The product under consideration on which duties are in force is ‘Melamine’.
8. The Designated Authority defined the scope of the product under consideration as follows in the Final Finding dated 01.06.2012:

“7. The product under consideration in the present petition is Melamine, a tasteless, odourless, and non-toxic substance. Melamine formaldehyde resin is used for laminates as it offers good hardness, resistance to scratch, stain, water and heat. Laminated used in some electrical applications possess high mechanical strength, good heat resistance and good electrical insulating properties. Asbestos filled Melamine resins possess very high dielectric strength and high resistance. Beside the best dimensional stability, Melamine Formaldehyde moulding powder gives clear and bright colours, easily mouldable and offers resistance to surface scratching. Melamine is reacted with formaldehyde and made into resins or moulding powder for making innumerable products of beauty and utility. Melamine is used for making melamine formaldehyde, which in turn is used in producing the downstream products.

8. The subject goods is classified under chapter 29 of the Customs Tariff Act at subheading no. 29336100. The customs classification is however is for reference purpose only and will have no binding on the scope of the present investigation.”

9. The petitioner has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the petitioner. As submitted by the petitioner, subject goods produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The petitioner has further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the petitioner in India as ‘Like Article’ to the product being imported from the subject countries

Domestic Industry

10. The present petition seeking sunset review of anti-dumping duties on subject countries is being filed by Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. Petitioner have claimed that they are the sole manufacturer of subject goods in India. The same was also the finding in the original investigation. The production of petitioners accounts for “a major proportion” in total production of the product under consideration in India. Petition therefore, satisfies standing and petitioners constitute Domestic Industry within the meaning of the Rules.

Initiation of Sunset Review

11. Having satisfied itself, on the basis of the positive *prima facie* evidence submitted by the domestic industry indicating likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury, the Authority hereby initiates a Sunset Review investigation in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of Antidumping Rules, to examine whether the expiry of the duties on the subject goods extended/imposed, vide customs notification No. 48/2012-Customs (ADD) dated 08.10.2012, would likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry and whether continued imposition of duties is warranted.

Subject Countries

12. The countries involved in the present investigation are European Union, Iran, Indonesia and Japan (referred to as the “subject countries”).

Normal Value

13. The petitioners have submitted that in the absence of availability of reliable information in the public domain on domestic prices of the subject goods in the subject countries, the Normal values in the subject countries have been estimated on the basis of cost of production; taking into account prevailing international prices of raw materials and conversion costs of the domestic industry, duly adjusted on account of selling, general & administration expenses, plus reasonable profit.

Export Price

14. The petitioner has claimed export price for the subject goods on the basis of DGCI&S published data. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges to arrive at net export price at ex-factory level. There is sufficient *prima facie* evidence with regard to the export price claimed by the petitioner.

Dumping Margin

15. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient *prima facie* evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are higher than the ex-factory export price, indicating that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. The dumping margin so estimated is above *de minimis* levels and is significant. In case of Indonesia, where there are no imports, the Authority has *prima facie* examined likelihood of dumping and injury.

Injury and Causal Link

16. Information furnished by the petitioner has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The petitioner has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production, price underselling and consequent significant adverse impact in terms of profits, return on capital employed and cash flow of the domestic industry. There is *prima facie* evidence of the ‘injury’ being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries and/or its recurrence on cessation of existing anti-dumping duty to justify initiation of a sunset investigation, to consider continuance of the existing ADD.

Period of Investigation (POI)

17. The period of investigation (POI) for the present investigation is from 1st April-2016 to 31st March 2017(12 months). However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e. Apr'13-Mar'14, Apr'14-Mar'15, Apr'15-Mar'16 and the period of investigation has been considered. Further, for likelihood analysis post POI data would be considered.

Submission of information

18. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce,
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,
New Delhi -110001.

19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time limit

20. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry’s application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of Information on Non-Confidential basis

22. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

23. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

24. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

28. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

29. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority